[श्री घन श्याम सिंह]

साथ ही गेहूं की बिक्री करने के सिलसिले में मैं खास तौर से एक बात कहना चाहता कि गेहूं खरीद केन्द्रों पर जैसे ही बाजार में किसान से गेहूं आना शुरू हुआ, गेहूं का भाव, जो सरकारी खरीद का भाव है, उससे भी कम होकर 125 से 130 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर पहुंच गया है और आज जब किसान गेहूं लेकर जाता है, तो आप जो सरकारी एजेंसियों से खरीद करा रहे हैं, वह केन्द्र भी पूरे तरीके से खोल नहीं पाए हैं, जितने खोलना चाहते थे, वह नहीं खुल पाये हैं। इसलिए जो गेहूं की आवक है केन्द्रों पर, वह इतनी ज्यादा हो गई है कि किसान दो-दो, तीन-तीन दिन तक वहां पड़ा रहता है और उसकी तुलाई नहीं हो पा रही है। जिसके कारण उसे मजबूर हो कर गेहूं फिर व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जो उसे सस्ते भाव पर लेते हैं और वही कर्मचारी जो सरकारी एजेंसियों पर हैं, उस गेहूं को सरकारी भाव पर व्यापारियों से खरीद करके ले लेते हैं। इस तरीके से व्यापारियों के द्वारा किसानों का शोषण हो रहा है और सरकारी अधिकारी जो इन केन्द्रों पर काम कर रहे हैं, वह भी उससे अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मैं विशेष कर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर सब से ज्यादा गेहूं पैदा होता है—बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, नैनीताल, इन जिलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां पर आप सख्त कदम उठायें जिसमें कि इन चीजों की कमी दूर हो पाए।

मैं चाहूंगा कि आप वहां सरकारी बोर्ड करें और कुछ अधिकारी भेजें—मैंने कृषि मंत्री जी से एक दिन बात की थी—तो उन्होंने कहा था कि जितनी गेहूं केन्द्रों पर आ जाती है, हम तो उसी को लेते हैं। तो आप जांच करवाएं कि गेहूं क्यों नहीं आ रही है? आखिर किसान उसको 125 रुपए पर बेचने को मजबूर हो जाता है, 152 रुपए पर क्यों नहीं देना चाहता? तो आप उसकी जांच करवायें और उस चीज को खोलने की कोशिश करें।

साथ ही जो बड़ा किसान है, वह नए गेहूं के साथ पुराना गेहूं भी आपकी एफ. सी. आई. को दे रहा है। उसका घुन लगा हुआ गेहूं तो लिया जा रहा है क्योंकि वह आपके कर्मचारी को रिश्वत दे देता है, लेकिन जो गरीब किसान है, वह यह सब नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह नहीं हो पा रहा है।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारी विद्युत आपूर्ति, डीजल की और सब से बड़ी भयंकर समस्या जो मैं आपको बताना चाहता हूं यह है कि उत्तर प्रदेश में बोरियों की कमी है—केन्द्रों पर बोरियां उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि एफ. सी. आई. बोरियों का वितरण करवा दे जिससे गेहूं की खरीद हो सके।

REFERENCE TO THE POWER CUTS RESORTED TO IN RAJASTHAN

श्री जसवंत सिंह (राजस्थान): माननीय उपसभापति जी, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि राजस्थान में बिजली की कटौती—वैसे बिजली का संकट पूरे उत्तर भारत में है, बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन राजस्थान में इसका संकट बहुत गम्भीर हो गया है। आज राजस्थान का जो उद्योग है, वह ठप पड़ा है, बिजली की कटौती शत-प्रतिशत है—

100 per cent power cut has been imposed on the industry in Rajasthan

और यह उद्योग का ही केवल होता, तो यहीं बात सीमित हो जाती, और अपने आप में इसी माल होता या कुछ महीनों के लिए समिति होता, तो भी राजस्थान उसको सम्भाल लेता। पर यह हर साल होता है, जब किसानों की बुआई के लिए या खेती के लिए बिजली की जरूरत होती है, तो बिजली नहीं मिलती। आज क्योंकि फसल कट चुकी है, राजस्थान इतना कृषि प्रधान प्रदेश नहीं है, कृषि को लेते हुए राजस्थान को बिजली की इतनी आवश्यकता नहीं है, समझ में नहीं आता कि इसके उपरान्त राजस्थान में शत-प्रतिशत उद्योग को लेकर कटौती क्यों की गई है।

इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि राजस्थान का अटामिक पावर प्लान्ट आर. ए. पी. पी. I और आर. ए. पी. पी. II

दोनों बन्द पड़े हुए हैं । उनकी वजह से आज इतनी बड़ी बिजली की कठिनाई और संकट राजस्थान को झेलना पड़ रहा है । उसके बारे में सदन में हर साल यही मसला उठता है और सरकार आश्वासन देती है पर हर साल कुछ नहीं हो पाता है ।

माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसके बारे में कुछ किया जाए ताकि उद्योग को कुछ तो बिजली मिले । शत-प्रतिशत पावर-कट में उद्योग कैसे चल सकेगा, यह भी आप ख्याल कर लें ।

REFERENCE TO THE ACUTE POWER SHORTAGE IN THE COUNTRY CAUING GREAT HARDSHIP TO ENTREPRENEURS

SHRI HUSEN DALWAI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to mention the following matter of urgent public importance.

Sir, in the entire country there is an acute shortage of power. The policy of the Government to encourage the industry has come to such a stage that the new entrepreneurs who have started their new undertakings are not getting power. They have been financed by the financial institutions. They are unable to pay the instalments and they want that they should be assured of this power. As a matter of fact, the Planning Commission and the Government of India have not visualised what would be the requirement of power when the policy of industrialisation was enunciated. In every State there are three districts which have been declared as backward districts. And there, an encouragement has been given by all financial institutions and new people have come to start industries, and they are progressing. The new proposals which have been taken in hand by the Government and by various Electricity Boards are lagging behind and their planning is still at a backward stage. And I don't think that they will be able to meet the requirements in a short time. As a matter of fact, there was a policy in between that the Government of India has taken a decision not to encourage hydro-electric projects because of investment. They were costly. But as a matter of fact the thermal projects which have been taken in hand, because of the short supply of coal, because of the non-availability of the wagons, these things have come in the way and there is acute shortage in every State. I would like to request the Government of India and especially the Ministry of Energy to take a note of this thing and see that these things which are taken in hand are expedited.

REFERENCE TO THE ALLEGED THREAT OF THE US GOVERNMENT TO WITHDRAW ITS MEMBERSHIP FROM UNESCO

श्री सैय्यद सिबते रजी (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेन्सी यूनेस्को से यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका ने अपनी सदस्यता छोड़ देने की जो धमकी दी है उस ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी इस उद्देश्य से कि दुनिया के देशों के अन्दर भाईचारा बढ़े और साथ ही साथ दुनिया के लोगों का जो जीवन स्तर है उस को किस तरह बढ़ाया जाय, जहां शिक्षा नहीं है वहां शिक्षा दी जाय । मान्यवर, आप जानते हैं कि दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या के लोगों के बच्चे आज स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं। यूनेस्को ने इस बात का फैसला किया कि 1980 तक 200 मिलियन बच्चों को स्कूलों में भेजने की व्यवस्था करेगी और उस के लिए सुविधाएं देगी । बहुत काफी कम हुआ है पिछले चन्द सालों के अन्दर चाहे वह संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च का क्षेत्र हो । ऐसी स्थिति में जो दुनिया में जनकल्याण के कार्यों में संस्था लगी हो उस का राजनैतिक दृष्टि से प्रयोग किया जाए और जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका ने निकल जाने की धमकी दी है उस से इस बात का पता